सत्यमेव जयते

पंचदश

बिहार विधान-सभा

एकादश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 21 अग्रहायण, 1935 (श0) / 12 दिसम्बर, 2013 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या-114

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	30
(2) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	15
(3) कृषि विभाग	..	..	16
(4) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	..	..	08
(5) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	12
(6) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	28
(7) सहकारिता विभाग	..	..	05
		कुल योग ..	114

स्ट्रीट लाईट लगाना

*281. श्री विनय कुमार सिंह---क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा नगर पंचायत में स्ट्रीट लाईट की सुविधा नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर पंचायत, दिघवारा में स्ट्रीट लाईट लगाने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

योजना पूरा कराना

*282. श्री सुदामा राय---क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज (जहांगीरा) में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों की जनता को शुद्ध पेय जलापूर्ति हेतु 80 लाख रुपये की लागत से मल्टी विलेज (बहुग्रामीण) जलापूर्ति प्रोजेक्ट पर काम एक वर्ष से चल रहा है, यदि हाँ, तो इस योजना को सरकार कबतक पूरा करने का विचार रखती है ?

भूमि उपलब्ध कराना

*283. श्री प्रमोद कुमार---स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 नवम्बर, 2013 को प्रकाशित शीर्षक "के0वि0वि0 खुलने पर लगा ग्रहण, अभिलेखागार में नहीं मिल रहे जमीन का कागजात भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी" के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी अंचल में स्थापित होने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालय के 301 एकड़ भूमि में 201 एकड़ भूमि गैर मजरूआ मालिक भूमि के रूप में चिन्हित हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बैरिया में चिन्हित गैर मजरूआ भूमि 124 एकड़ 97 डी0 भूमि में खेसरा नं0 3,4,6, 9,11,14,10,20,276,553,279,460,461,464,465,466,467,468,470,458,383,384,382,33,39,124 में पेंच फंसा हुआ है, जिसके कागजात मोतिहारी अभिलेखागार से लेकर बेतिया राज कार्यालय सहित मोतिहारी अंचल तक भू-माफियों द्वारा सरकारी अधिकारी व कर्मचारी को मिलाकर कागजात गायब करा दिया गया है, यदि हाँ, तो उक्त पेंच को दूर कर अविलम्ब केन्द्रीय विश्वविद्यालय को भूमि उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

महादलित परिवारों को जमीन देना

*284. श्रीमती आशा देवी---क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत दानापुर प्रखण्ड में बाढ़ के कारण हुए कटाव से पुरानी पानापुर के महादलित पीड़ित परिवार आज भी प्रखण्ड परिसर, दानापुर में प्लास्टिक का झोपड़ी बनाकर सैकड़ों परिवार रह रहे हैं, यदि हाँ, तो कटाव से विस्थापित इन परिवारों को महादलितों को वास जमीन का प्रावधान के तहत भूमि देने का सरकार विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

बचे कार्य को पूरा कराना

*285. श्रीमती नीता चौधरी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर प्रखण्ड अन्तर्गत कमरगामा, खैरा एवं बैजलपुर में मिनी जलापूर्ति के अन्तर्गत सिर्फ बोरिंग का कार्य हुआ है, यदि हाँ, तो बाकी बचे कार्य को सरकार कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*286. श्री (डॉ0) अब्दुल गफूर—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012–13 में सहरसा जिलान्तर्गत नवहट्टा महिषी एवं सतर कटैया प्रखंडों में मुख्य मंत्री चापाकल योजना द्वारा संवेदक को कार्य आवंटित हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा 50 प्रतिशत चापाकल बिना चबूतरा एवं नाला के गाड़ा गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्राक्कलन के अनुकूल कार्य नहीं कराया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्थलीय जाँच कराकर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति चालू कराना

*287. श्री श्रवण कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत राजगीर प्रखण्ड में मिनी जलापूर्ति योजनान्तर्गत निर्मित खैला सलारू, डुमरी, कुरथौर, बढ़ौना में पेयजल आपूर्ति बन्द है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलापूर्ति के बन्द होने से उक्त ग्रामों में पेय जल संकट उत्पन्न हो गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बन्द जलापूर्ति को चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*288. श्री अशोक कुमार—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर प्रखंड के बाँसघाट मसूरिया पंचायत के गैर–मजरूआ मलिकान भूमि खाता नं0 547, खेसरा 1361, रकवा 1 कट्ठा 12 धूर भूमि का अतिक्रमण कैलाश राय, पिता चरितर राय, ग्राम बाँसघाट मसूरिया तथा सर्वे नं0 644 आम गैर–मजरूआ भूमि का अतिक्रमण सुदर्शन राय, पिता गली राय, ग्राम बाँसघाट मसूरिया द्वारा कर ली गई है, जिसमें आम जनता का रास्ता अवरूद्ध हो गया है ;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार अतिक्रमण को कबतक मुक्त करना चाहती है ?

राशि उपलब्ध कराना

*289. श्री प्रदीप कुमार---क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे प्रदेश के कृषकों को कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013–14 में नवादा जिला सहित पूरे प्रदेश के सभी जिलों को कृषि यंत्रों की अनुदान की राशि अप्राप्त है, जिससे कृषकों को कृषि यंत्र खरीद करने में काफी परेशानी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्ष 2013–14 का कृषि यंत्रों का अनुदान की राशि कबतक जिला कृषि कार्यालयों को उपलब्ध करवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

गोदाम की मरम्मती

*290. श्री संजय सिंह टाईगर---क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत संदेश प्रखण्ड के संदेश में विस्कोमान का गोदाम अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गोदाम के जर्जर हालत में होने के चलते भंडारण सम्भव नहीं है, जिससे किसानों को परेशानी होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विस्कोमान गोदाम की मरम्मती करा उसे भंडारण योग्य बनाना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पार्क को कचरा मुक्त करना

*291. श्री अरूण शंकर प्रसाद---स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 अप्रैल, 2013 को प्रकाशित शीर्षक "36 में सिर्फ तीन पार्क चकाचक" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है राजधानी पटना के 36 पार्कों में से मात्र तीन शिवाजी, लोहिया एवं चिल्ड्रेन पार्क अच्छी स्थिति में है तथा शेष 33 पार्क गंदगी एवं कचरा से भरा हुआ है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

निर्माण कराना

*292. डॉ0 इजहार अहमद---क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत हारूण नगर सेक्टर 11 में खुजाई इमली मजार से अमन कॉलोनी, बजरंग बली कॉलोनी होते हुए प्रश्नकर्त्ता के घर तक सड़क की हालत काफी जर्जर है एवं सड़क के किनारे नाला नहीं रहने के कारण सड़क पर दो से तीन फीट पानी लगा रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मती एवं नाला का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाली का निर्माण

*293. श्री राज कुमार राय—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर विधान–सभा के सभी पंचायतों में विधायक के अनुशंसा पर प्रति पंचायत पाँच–पाँच चापाकल गड़वाया गया है, परन्तु चापाकल का प्लेटफार्म एवं नाली निर्माण अभीतक संवेदक के द्वारा नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

पशु चिकित्सालय नहीं रहने का औचित्य

*294. श्री कृष्णनन्दन यादव—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के नीमचक बथानी अनुमंडल के कई गाँव गया शहर से 80–90 कि०मी० के दूरी पर बसा हुआ है, परन्तु यहाँ एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

पेयजल की सुविधा

*295. श्री अरूण मांझी—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत, मसौढ़ी नगर परिषद् क्षेत्र में पेयजल सुविधा हेतु पम्प हाउस तो है लेकिन न तो पाइप लाइन पूरी तरह चालू है और न ही जलमीनार है, यदि हाँ, तो उक्त समस्या का निपटारा हेतु सरकार की क्या योजना है ?

कार्य पूर्ण कराना

*296. श्री अमन कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत, पीरपैंती प्रखंड के ग्राम मलकपुर, धोबी टोला, धुनिया चक, पीरपैंती पहाड़, दुधैली, हुजुरनगर एवं अकबरपुर में वर्ष 2010 में विभाग द्वारा मिनी पाइप वाटर सप्लाई योजना के तहत उक्त ग्रामों में पाइप लाइन बिछाकर जलापूर्ति करने की स्वीकृति दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलापूर्ति योजना को पूर्ण करने हेतु विधिवत निविदा निकाल कर संवेदक द्वारा कार्य कराया जाना था ;

(3) क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा उक्त जलापूर्ति योजना के कार्य को बिना पूर्ण किये ही 80 प्रतिशत राशि की निकासी कर ली गयी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में कबतक कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी मुहैया कराना

*297. श्री प्रेमरंजन पटेल—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लक्खीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा प्रखंड के बुधौलीबनकर तथा उरैन पंचायत में पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बुधौलीबनकर तथा उरैन पंचायत के लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना का स्वीकृति वर्ष 2007–08 में ही दिया जा चुका है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अभीतक लोगों में पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सका है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बुधौलीबनकर तथा उरैन पंचायत के लिए स्वीकृत जलापूर्ति योजना को पूर्ण कराकर पीने का पानी मुहैया कराने का विचार रखती है, अगर हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सक पदस्थापित नहीं करने का औचित्य

*298. श्री अख्तरूल ईमान—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के प्रखंड कोचाधामन में मात्र एक ही पशु चिकित्सालय है, जिसमें विगत सात वर्षों से कोई भी चिकित्सक पदस्थापित नहीं किए गये हैं, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

वंचित रखने का औचित्य

*299. श्री जाकिर हुसैन खान—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिले के अररिया के वार्ड नं० 3 आर०एस० बस्ती, वार्ड नं० 29 मरियाटोला, वार्ड नं० 11 खरिया बस्ती, डमहैली, वार्ड नं० 1, 2 रेकपुर पटियारी मटियारी, वार्ड नं० 20 सिसौना, वार्ड नं० 18 बारीदत, वार्ड नं० 7, 8 अलीनगर, उमरनगर, जय प्रकाश नगर इत्यादि वार्डों में नगर परिषद् का दर्जा 1997 में प्राप्त होने के बावजूद भी बिजली, सड़क एवं जलापूर्ति से वंचित रखा गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

पाइप लाइन जोड़वाना

*300. श्री जवाहर प्रसाद—–क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर के मुहल्ला मदार दरवाजा मे जलापूर्ति पाइप लाइन नही जोड़ने के कारण नगर के मुहल्ला नवरतन बाजार, महाजनटोली, काजीपुरा, शहजुना इत्यादि मुहल्ले के लोगों को पिछले 50 वर्षों से जलापूर्ति बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रोहतास जिला के मदार दरवाजा मे जलापूर्ति पाइप लाइन जोडवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यो ?

शुद्ध जल उपलब्ध कराना

*301. श्री जनार्दन माझी—–क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत बाँसी प्रखंड के सुखनिया जलापूर्ति योजना करीब बीस वर्षों से बन्द है, जिसके कारण 50 हजार आबादी को शुद्ध पीने का जल नही मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित मे उक्त योजना को चालू कर शुद्ध जल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार चालू कराना

*302. श्री महेश पासवान—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत, कोढ़ा प्रखंड मुख्यालय एवं कोढ़ा प्रखंड के मुसापुर में वर्ष 2012 में जलमीनार का निर्माण कराया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जलमीनार को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*303. श्री (मो०) आफाक आलम—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के कसबा नगर पंचायत के महावीर चौक से युकार टोला होते हुए बर्फ फैक्ट्री पीच रोड तक सडक का निर्माण आजतक नही किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

पशु अस्पताल बनाना

*304. श्रीमती (डॉ०) रंजु गीता—–क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड स्थित मधुबन बराहा (पश्चिमी) पंचायत मे प्रखंड के सर्वाधिक पशुपालक रहते है, परन्तु पशु चिकित्सालय नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार यहाँ पशु अस्पताल बनाने का विचार रखती है ?

खाद उपलब्ध कराना

*305. श्री अख्तरुल ईमान--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में रब्बी फसल के लिये केवल 5,000 (पाँच हजार) मिट्रीक टन रासायनिक खाद की आपूर्ति की जाती है जबकि जिला के किसानों को 40,000 (चालीस हजार) मिट्रीक टन यूरिया की आवश्यकता है, यदि हाँ, तो बाकी 35,000 मिट्रीक टन रासायनिक खाद किशनगंज जिला को उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

सड़क की स्थिति सुधारना

*306. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत, शेरघाटी के नई बाजार महादलित टोला से महुआटांड तक सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है, यदि हाँ, तो उक्त सड़क की स्थिति सुधारने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

राशि खर्च करना

*307. श्री प्रमोद कुमार--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013-14 में मुख्य मंत्री शहरी विकास योजना अन्तर्गत आठ करोड़ 72 लाख रुपये पूर्वी चम्पारण जिला को राशि आवंटित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर विकास विभाग द्वारा अभीतक योजनाओं का चयन नहीं किया गया है और ना ही इस संबंध में बैठक ही किया गया है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो जनहित में सरकार आवंटित राशि से पूर्वी चम्पारण जिला में पुल-पुलिया, सड़क, सामुदायिक भवन, सीढ़ी, घाट, पार्क आदि पर राशि खर्च करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दवा उपलब्ध कराना

*308. डॉ० फैयाज अहमद--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखण्डान्तर्गत पशु अस्पताल में एक साल से पशुओं की कोई दवा उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो दवा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

कृषकों का भुगतान

*309. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009-10 में पूर्वी चम्पारण जिले के 41,998 गैर-ऋणि कृषकों द्वारा कराये गये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति की 82.24 करोड़ रुपये की राशि भुगतान हेतु जाँच कराकर योग्य कृषकों को भुगतान का निर्णय लिया गया था, लेकिन अबतक 10 प्रतिशत किसान को भी भुगतान नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो भुगतान में विलम्ब का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2009-10 में खरीफ मौसम के लिये सभी 15,971 गैर-ऋणी कृषकों को कुल 34.29 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा चुका है ।

जहाँतक रब्बी मौसम के 52.24 गैर-ऋणी किसानों को 137.29 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का प्रश्न है, इस संबंध में बीमा कम्पनी द्वारा समर्पित दावा राशि में कतिपय त्रुटियाँ पाई गई, जैसे वास्तविक आच्छादन क्षेत्रफल से कहीं ज्यादा क्षेत्रफल का बीमा किया गया है । इसपर बीमा कम्पनी द्वारा सम्पुल जाँच कर संशोधित दावा समर्पित करने का आश्वासन दिया गया है, जो अभीतक अप्राप्त है, जिसके कारण भुगतान बाधित है ।

बीमा कम्पनी से जाँच प्रतिवेदन एवं संशोधित दावा प्राप्त होने पर ही राज्यांश की राशि विमुक्त की जा सकेगी ।

विरमित नहीं करने का औचित्य

*310. श्री जय कुमार सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिले में 8 उद्यान सेवकों का स्थानान्तरण कर दिया गया है, जिसमें 7 को विरमित कर दिया गया है, यदि हाँ, तो शेष अनुसेवक को विरमित नहीं करने का क्या औचित्य है ?

स्थानान्तरित करना

*311. श्री राजेश्वर राज--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य खाद्य निगम में जिला प्रबंधक का पद राज्यस्तरीय है, जिसका स्थानान्तरण तीन वर्ष पर किये जाने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि बक्सर, भोजपुर एवं भभुआ जिलों में जिला प्रबंधक पद पर विगत 6 वर्षों में कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बक्सर, भोजपुर एवं भभुआ जिलों में 6 वर्षों से अधिक दिनों से पदस्थापित जिला प्रबंधकों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध जल उपलब्ध कराना

*312. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर, लखनपुर में चापाकल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा पाया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शुद्ध जल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

क्रियान्वयन कराना

*313. श्री सुबोध राय--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम के सौन्दर्यीकरण हेतु गंगा नदी के किनारे भागलपुर जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा समर्पित डी०पी०आर० विगत छः माह से संबंधित विभाग में लम्बित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त उक्त योजना का क्रियान्वयन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

हाई मास्क लाइट चालू करना

*314. श्री सुरेश कुमार शर्मा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 2009-10 में शहर में करोड़ों रुपये की लागत से 22 हाई मास्क लाइट का निर्माण कराया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी हाई मास्क लाइट के जाँचोपरान्त जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा दिनांक 20 अप्रील, 2012 को मुजफ्फरपुर नगर निगम को अधिग्रहण करा दिया गया, परन्तु इसे अभीतक चालू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

अनुमोदन प्राप्त करना

*315. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के अधीन पहाड़ी पूर्वी जोन सेक्टर नं० 5, थाना नं० 14 क्षेत्र के नागरिकों द्वारा वर्ष 2009 में ही अपने प्लॉट पर निर्माण हेतु नक्शा अनुमोदन कराने के लिये आवेदन नगर निगम में दिया गया था, परन्तु अभीतक अनुमोदन अप्राप्त है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

कानूनी कार्रवाई करना

*316. श्री भोला राय--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नूतन राजधानी प्रमंडल (उत्तरी) पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक 245 सी०, दिनांक 22 अगस्त, 2012 से गठित टीम द्वारा बोरिंग कैनाल रोड स्थित सिसौदिया पैलेस (व्यावसायिक) एवं एम्बियंस पार्क (आवासीय) भवन का दिनांक 31 अगस्त, 2012 को निरीक्षण एवं मापी में पटना नगर निगम के प्रावधान के विपरीत निर्माण कार्य पाया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्माता द्वारा निर्माणाधीन भवनों का पटना नगर निगम से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिए ही अधिकांश हिस्सों को बेच दिया गया है, जिसमें लोग भी आवासित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध निर्माण कार्य करने एवं फ्लैट को बेचने वाले निर्माता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सब्जी मार्केट का निर्माण

*317. श्री अरुण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना के कंकड़बाग में टेम्पू स्टैंड के समीप नगर निगम अंचल कार्यालय के पास खाली पड़े जमीन पर सब्जी मार्केट के निर्माण के लिए 17 लाख रुपये की स्वीकृति जनवरी, 2008 ई०, में दिये जाने के बावजूद इसका निर्माण कार्य अबतक शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इस सब्जी मार्केट के निर्माण कार्य को कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्त्ति योजना पूर्ण कराना

*318. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के अस्थावां विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत बिन्द प्रखण्ड, सरमेरा प्रखण्ड और कतरी सराय प्रखण्ड मुख्यालय में वर्ष 2006-07 में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा उक्त योजना में वर्ष 2008-09 में पूरा किया जाना था जो आजतक अधूरा पड़ा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

भूमि को मुक्त कराना

*319. श्री भोला राय--क्या मंत्री, पशुपालन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कदवा प्रखंडान्तर्गत श्रीमती पूर्णिमा देवी गोशाला सेनाली के (पास 115) एक सौ पन्द्रह एकड़ भूमि है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गोशाला की आबादी भूमि वर्षों पूर्व अन्न लीज प्रति क्विंटल/प्रति एकड़ की दर से लीजधारी किसानों को दिया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त लीजधारी किसान नये लीज दर पर खेती करने के बजाय उक्त खेतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन लीजधारियों से भूमि को मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

सब्सिडी घटाने का औचित्य

*320. डॉ० फैयाज अहमद--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला सहित पूरे राज्य में गेहूँ बोआई हेतु जीरो टील्लर मशीन की खरीद पर सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी 90 प्रतिशत से घटा दी गयी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

*321. श्री अवनीश कुमार सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार भूगर्भ जल अधिनियम, 2006 (विकास एवं प्रबंधन तथा संचालन एवं नियंत्रण) के अनुसार एक हजार वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्र में बनने वाली इमारतों में आवश्यक रूप से रूफ-टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के बाद ही नक्शा पास किया जाना है, परन्तु राज्य के 1000 वर्ग मीटर वाली किसी भी इमारत में रूफ-टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग नहीं रहने के बावजूद धड़ल्ले से नक्शा पास किया जा रहा है, यदि हाँ, तो कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

एन०बी०आई० योजना का लाभ

*322. श्री जय कुमार सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि एन०बी०आई० योजना के तहत वैशाली जिला उद्यान कार्यालय द्वारा जिस प्रखण्डों में पिछले वित्तीय वर्ष 2011-12 में किसानों को इसका लाभ दिया गया उसी प्रखण्ड को इस वित्तीय वर्ष में भी महुआ, पातेपुर, जन्दाहा, भगवानपुर, राघोपुर सहित 5-7 प्रखण्डों को दिया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

दोषी पर कार्रवाई

*323. श्रीमती देवंती यादव--क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड के फरही ग्रामवासी अक्षय लाल ऋषिदेव, पिता-अगहनु ऋषिदेव को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के माध्यम से 1956 में श्रीमती लीलावती देवी, पति-मोहन लाल मंडल, ग्राम-कनैली द्वारा खाता सं० 2, खेसरा 1427, 1428, 1429 रकवा 1 एकड़ 21 डी० जमीन दान में दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी, नरपतगंज द्वारा गलत तरीके से उसी खाता एवं खेसरा का 1 एकड़ 98 डिसमील जमीन श्रीमती अर्चना देवी पति-सुनील सिंह से क्रय कर 66 महादलितों में बाँटा जिस पर आजतक कब्जा नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्रय किये गये जमीन की जाँच कर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शीत गृह बनाना

*324. श्री रामसेवक सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के विधान-सभा क्षेत्र में प्याज रखने हेतु शीत गृह नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों के हित में शीत गृह बनाने का विचार रखती है ?

बाकी पदों को भरना

*325. श्री अरूण मांझी--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि समन्वयक के 4391 पद में से करीब आधे पद अभी भी रिक्त हैं, यदि हाँ, तो बाकी पदों को भरने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

समस्या दूर करना

*326. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी के वार्ड नं० 3 एवं वार्ड नं० 4 के महादलित टोलों में जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो इसे दूर करने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

कार्रवाई करना

*327. श्री (मो०) जावेद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज विधान-सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री शहरी विकास योजना अन्तर्गत पुरनटोगल स्कूल से तगरया पानी टंकी तक नाला निर्माण में भारी गड़बड़ी हुई है एवं निर्माण कार्य में बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच हेतु सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

अनाज का वितरण

*328. श्री जाकिर हुसैन खान--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिले के अररिया प्रखंड के सभी पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों में 13 मार्च, 2013 से ही ए०पी०एल० परिवार वाले लाभार्थियों को अनाज वितरण हेतु उठाव नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनाज का उठाव कराकर वितरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*329. श्री सुरेश कुमार शर्मा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर शहर अन्तर्गत वार्ड संख्या 2 में राहुल नगर से देवरिया रोड तक पथ एवं नाला निर्माण की स्वीकृति जिला संचालन समिति द्वारा वर्ष 2011-12 में ही दे दी गयी;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वीकृति के उपरांत विभाग के कार्यकारी एजेंसी डुडा द्वारा उक्त सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया;

(3) क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा निर्माण कार्य को शुरू करने के दो-तीन दिन बाद ही निर्माण कार्य बंद कर दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक खंड (1) में वर्णित सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है ?

मुआवजा देना

*330. प्रो० चन्द्रशेखर--हिन्दी दैनिक पत्र के दिनांक 20 जनवरी, 2013 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "मक्का को 40 फीसदी नुकसान" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अत्यधिक ठंड के कारण मधेपुरा जिला में 6,000 (छ: हजार) एकड़ में लगी मक्का की फसल बर्बाद हो गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मक्का फसल के बर्बाद से पीड़ित किसानों को समुचित मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

किसान भवन का निर्माण

*331. श्री अजीत कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में राज्य के सभी प्रखंडों में ई० किसान भवन निर्माण कराने का निर्णय वित्तीय वर्ष 2008-09 में लिया था;

(2) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी एवं मरवन प्रखंड में सरकार के उपर्युक्त निर्णय के पाँच वर्ष बाद भी ई० किसान भवन का निर्माण नहीं हो सका है, जबकि उक्त दोनों प्रखंडों में भवन निर्माण के लिये सरकारी जमीन उपलब्ध है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक प्रश्नगत प्रखंडों में ई० किसान भवन का निर्माण कराना चाहती है ?

दोषी पर कार्रवाई

*332. श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सफाई उपकरण खरीदन के नाम पर वर्ष 2013 में सफाई उपकरण की खरीद की गयी वो घटिया स्तर का है एवं मानक के अनुरूप नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध नहीं कराने का औचित्य

*333. श्रीमती मुन्नी देवी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 869, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 से आदेश निर्गत है कि माननीय सदस्यों के लिखे पत्र पर पत्र प्राप्ति की सूचना 15 दिनों में एवं कृत कार्रवाई से एक माह के अन्दर अवगत कराया जाय;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 112/13, दिनांक 23 अगस्त, 2013 के प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार सरकार को पत्र दिया गया, लेकिन आजतक कृत कार्रवाई से अवगत कराना तो दूर पत्र प्राप्ति की सूचना तक नहीं दिया गया;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सूचना उपलब्ध नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

नलकूपों की मरम्मती

*334. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर और बारून प्रखंड के अलग-अलग गाँवों और टोलों में पेयजल चापाकल भारी संख्या में खराब हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उन खराब नलकूपों का मरम्मती कराकर चालू कराने का विचार रखती है ?

पानी टंकी चालू कराना

*335. श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के रिविलगंज नगर पंचायतान्तर्गत तीन स्थानों पर पानी टंकी बनकर तैयार है, यदि हाँ, तो उसे अभीतक चालू नहीं करने का क्या औचित्य है ?

जमीन उपलब्ध कराना

*336. श्रीमती नीता चौधरी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर प्रखंड अन्तर्गत पंचायत दरियापुर II के ग्राम मधुवन के 200 महादलित परिवारों को प्रावधान के बावजूद अभीतक आवास हेतु जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

योजना पूर्ण करना

*337. श्री रामचन्द्र सहनी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारणान्तर्गत प्रखंड कार्यालय, सुगौली के परिसर में 1996 में विभागीय स्तर से सार्वजनिक पेय जलापूर्ति हेतु बोरिंग की स्थापना की गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि बोरिंग से संबंधित जलभंडार तथा पाइप लाइन का निर्माण के अभाव में 32 हजार से अधिक जनसंख्या सार्वजनिक स्वच्छ पेय जलापूर्ति की सुविधा से वंचित हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त अधूरे योजना को राज्य योजना मद से पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यों की जाँच

*338. श्री शिवजी राय--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के मधुबनी विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रखंडों में वित्तीय वर्ष 2010-11, वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में प्राक्कलन के विरुद्ध नये चापाकलों को मात्र 140 फीट से लेकर 170 फीट के बीच में ही बोरिंग किया गया है तथा उक्त गाड़े गये सभी चापाकलों पर पानी नहीं निकलता है तथा आजतक चबूतरा का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि 40 लाख रुपया का इसपर व्यय किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जाँच निगरानी विभाग से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*339. श्री सुरेश चंचल--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना सदर प्रखंड के जक्कनपुर थानान्तर्गत पुरन्दरपुर मोड़ (पोस्ट ऑफिस के निकट) से छपरा कॉलनी मोड़ होते हुये चाँदपुर बेला, दोपुलवा शिव मंदिर तक जाने वाली पथ के दोनों साईड गैर-मजरूआ सरकारी जमीन अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करा लिया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ के दोनों किनारे के गैर-मजरूआ सरकारी जमीन की मापी कराकर अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना शुरू नहीं कराने का औचित्य

*340. श्री संजय कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में सरकार ने बिहार के किसानों को खाद एवं कीटनाशक दवाओं के नये-नये शोध से अवगत कराने एवं उन्हें प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि कृषकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2012 में केवल पटना एवं नालन्दा जिला में ही शुरू किया है, यदि हाँ, तो वैशाली सहित राज्य के अन्य जिलों में इस योजना को शुरू नहीं करने का क्या औचित्य है ?

शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना

*341. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास प्रखंड स्थित ग्रामीण जलापूर्ति योजना, बिसौल, करही एवं फुलपरास तथा घोघरडीहा प्रखंड स्थित शहरी जलापूर्ति योजना, घोघरडीहा तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, मधेपुर प्रखण्ड मुख्यालय से आम जनता को वर्ष 2006 से एक बूंद भी शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं हो रहा है तथा उस योजना में लग 91.0983 लाख की लागत व्यर्थ साबित हो रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

मँहगाई पर रोक

क*342. श्री दिनेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आलू एवं प्याज का मूल्य इन दिनों चालीस से 90 रुपया प्रति किलो तक हो गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार बढ़ती मंहगाई पर तत्काल रोक लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण हटाना

*343. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत सिधवलिया प्रखंड-सह-अंचल के मौजे सुपौली के श्री कपिलदेव सिंह द्वारा गैर-मजरूआ भूमि खाता नं० 435, सर्वे नं० 499, थाना 402, रकबा 90 डिसमील भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे नवसृजित प्रा० विद्यालय का भवन निर्माण मौजे सुपौली में नहीं हो पा रहा है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार गैर-मजरूआ भूमि से अतिक्रमण कबतक हटाने का विचार रखती है ?

पदस्थापन का विचार

*344. श्री वैद्यनाथ सहनी--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड मोरवा में प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पद एक वर्ष से रिक्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पदस्थापन का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । श्री ब्रजकिशोर शर्मा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मोरवा, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित हैं ।

नोट--(क) वित्त विभाग के ज्ञापांक 11873, दिनांक 26 नवम्बर, 2013 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में स्थानान्तरित ।

सुधा डेयरी केन्द्र की संख्या बढ़ाना

*345. श्री रमेश ऋषिदेव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सुधा डेयरी का उत्पादन बिक्री केन्द्र 16 लाख की जनसंख्या में मात्र चार बूथ केन्द्र है, जिससे अन्य जिला को सुधा डेयरी का दूध मिलने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सुधा डेयरी का उत्पादन बिक्री केन्द्र खोलने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से जमीन आवंटन करने हेतु सुधा के पदाधिकारी ने एक वर्ष पूर्व ही जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से अनुरोध किया है, परन्तु अबतक नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपभोक्ता के उपयोगार्थ शीघ्र सुधा डेयरी केन्द्र की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

भवन का निर्माण

*346. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंडाधीन शालमारी में पशु चिकित्सालय की मंजूरी विगत वर्ष 2009 में की गई है, परन्तु भवन के अभाव में पशुओं की इलाज बाधित है, यदि हाँ, तो उक्त भवन निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

कार्रवाई करना

*347. श्री विक्रम कुँवर--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 नवम्बर, 2013 को प्रकाशित ''अनाज खरीद का नया इंतजाम'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान और सारण में अनाज उठाव में गड़बड़ी की जाँच आर्थिक अपराध इकाई से करवाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया, परन्तु आजतक उसपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिसके चलते उक्त जिलों के आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसको जाँचकर दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जाँच

*348. डॉ० (मो०) जावेद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं० 8 के तेघरिया में शहरी विकास योजनान्तर्गत नाला निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो उक्त नाला निर्माण में हो रही अनियमितता की जाँच हेतु सरकार की क्या योजना है ?

तेल डिपो खोलना

*349. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005-06 में किशनगंज जिला में 4 किरासन तेल का डिपो था, वर्तमान में केवल दो ही डिपो है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड ठाकुरगंज में भी तेल का डिपो बन्द है ;

(3) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के प्रखण्ड ठाकुरगंज के डीलरों को तेल उठाव के लिये 50 कि०मी० दूर बहादुरगंज जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो उक्त समस्याओं के निदान हेतु सरकार की क्या योजना है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ठाकुरगंज के तेल डिपो को चालू करते हुये जिला किशनगंज में दो और डिपो को खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना

*350. श्री (डॉ०) अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के अंक में छपी खबर ''किसानों से भाग रही नयी पीढ़ी'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि प्रधान राज्य में कृषि के लाभकारी नहीं होने के कारण राज्य की युवा पीढ़ी कृषि से विमुख हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि के विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है और इससे किसानों को कृषि में घाटा होता है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिये संरक्षण एवं विपणन हेतु क्या कार्य योजना है ?

अवैध कब्जा से मुक्ति

*351. श्री श्रवण कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के मानसी थाना स्थित खिरिनियाँ गाँव के खाता संख्या 23 तथा 31, खेसरा नं० 31, 32, 39, 54, 62 एवं 77 तौजी नम्बर 1380 अराजी 23 बिगहा 1 कट्ठा 5 धुर जमीन है जो मो० ईसराइल, मो० गुफर, मो० एकरामूल, मो० मुनीद एवं सनजीता खातुन की जमीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी प्लौटों पर अवैध रूप से ग्राम-सैदपुर, थाना-मानसी के निवासी विजेन्द्र यादव, धर्मेन्द यादव, जितेन्द्र यादव, चौरसिया यादव के द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा जमाये हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध कब्जा से जमीन को मुक्त कराकर इसे जमीन मालिकों को दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

कचरा मुक्त कराना

*352. श्री रामसेवक सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दुल्हिन बाजार प्रखंड के शहीद जगदेव चौक स्थित अमर शहीद जगदेव प्रसाद स्मारक के प्रांगण में काफी गंदगी एवं कचरा जमा हो गया है, जिससे वहाँ के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि जिलाधिकारी, पटना के ज्ञापांक 813, दिनांक 29 जनवरी, 2008 द्वारा एस०डी०ओ०, पालीगंज को उचित कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया था, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रांगण को गंदगी एवं कचरा से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल मीनार चालू कराना

*353. श्री विनोद कुमार सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के आजमनगर प्रखण्ड अन्तर्गत प्रखण्ड मुख्यालय, आजमनगर में वर्ष 2011 में निर्मित जल मीनार को चालू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, इसे चालू कराने का विचार रखती है ?

पानी उपलब्ध कराना

*354. श्री नौशाद आलम—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि ठाकुरगंज एवं दिघल बैंक सहित सभी प्रखण्ड वासियों को आयरन युक्त पानी पीना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि आयरन युक्त पानी पीने के कारण क्षेत्र के लोग विभिन्न प्रकार के बीमारी से ग्रसित हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ठाकुरगंज प्रखण्ड के 1. राजीवबस्ती छैतल 2. मसानी 3. भोग-डाबर मुख्या टोला 4. दूधऔंटी 5. नेमुगुड़ी 6. भवानीगंज 7. कौआभीठा 8. डोंगिगच्छ 9. धूमगढ़ 10. सुहागी एवं दिघल बैंक प्रखण्ड के हरजुल्ला एवं मंगूरा आदि स्थानों में आयरन मुक्त पानी उपलब्ध कराने का सरकार विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*355. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नगर परिषद् समस्तीपुर क्षेत्र के बहादुरपुर स्टेशन रोड लेक टाउन कॉलोनी में पानी का बहाव एवं जलग्रहण क्षेत्र हसनपुर, बहादुरपुर एवं मालगोदाम के निकट वाला चौर है;

(2) क्या यह बात सही है कि वार्सिंगकोट के निकट दो फीट ऊपर कल्वर्ट व नाला (1000) बना दिये जाने के कारण उक्त क्षेत्र के पानी का बहाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और पानी उपजाऊ खेतों से घरों में प्रवेश कर रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जल निकासी हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

सड़क की पक्कीकरण

*356. श्री (प्रो०) चन्द्रशेखर—हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2013 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "कहने को नम्बर वन वार्ड, सुविधाओं में फिसड्डी" के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला मुख्यालय एन०एच० 106 विद्युत् पावर सब-स्टेशन के पास से जो सड़क नौलखिया गाँव जाती है, वह कच्ची एवं जर्जर अवस्था में है, यदि हाँ, तो जनहित में उक्त सड़क की पक्कीकरण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

सैरात कराना

*357. श्री प्रेम कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही अंचल के हनुमान नगर गाँव में एक सरकारी तालाब जो निर्मली पोखर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका खाता नं० 89, खेसरा नं० 618 कुल रकवा 2 बिगहा ग्यारह कट्ठा 13 धूर है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त पोखर को सैरात कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*358. श्री प्रदीप कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावाँ प्रखण्ड के पकरीबरावाँ बाजार में वारिसलीगंज मोड़ पर शुलभ शौचालय/सामुदायिक शौचालय नहीं है, यदि हाँ, तो प्रावधान के आलोक में वहाँ शौचालय निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

जल मीनारों का निर्माण

*359. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु मात्र दो जल मीनारों का निर्माण हो रहा है, जो 2 लाख आबादी के लिए अपर्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार कितने और जल मीनारों का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

अंचलाधिकारी की प्रतिनियुक्ति

*360. श्री दुलालचन्द्र गोस्वामी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई अंचल में विगत 9 महीना से अंचलाधिकारी का पद रिक्त है, तो क्या सरकार उक्त अंचल में अंचलाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पानी उपलब्ध कराना

*361. श्री प्रेम रंजन पटेल--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला अन्तर्गत सूर्यगढ़ा प्रखण्ड के पंचायत ताजपुर रिता, किरणपुर अनगिल रामपुर, कथादपुर, रामपुर, चन्दनपुरा, टोरलपुर, महम्मदपुर मलीनगर में भू-जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से लोगों को कई प्रकार के रोग से ग्रसित हो रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि आर्सेनिक प्रभावित पंचायतों को सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजना के माध्यम से शुद्ध जल मुहैय्या कराती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित पंचायतों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के माध्यम से शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*362. श्री राम प्रवेश राय--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखण्ड मुख्यालय में अवस्थित सरकारी अस्पताल की जमीन का कुछ भाग वर्ष 1985 से ही अतिक्रमण कर लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि अस्पताल परिसर के जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने हेतु अंचल पदाधिकारी, बरौली ने अपने पत्रांक 4, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज से दण्डाधिकारी के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल की मांग की थी, किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया;

(3) क्या यह बात सही है कि समाहर्त्ता, गोपालगंज ने भी अपने पत्रांक 162, दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 द्वारा उक्त अस्पताल परिसर को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का आदेश दिया है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त अस्पताल की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं विलम्ब के लिये जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*363. श्रीमती सुनीता सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बेलसंड अनुमण्डल मुख्यालय स्थित पानी टंकी का पाँच वर्षों से जलापूर्ति ठप है, जिसके कारण पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय उदासीनता के कारण वर्षों पुराना पानी टंकी जर्जर होने के कारण टंकी से पानी रिसता रहता है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पानी टंकी की मरम्मती एवं साफ-सफाई कराकर जलापूर्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फौगिंग की व्यवस्था

*364. श्री (डॉ०) इजहार अहमद— स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 नवम्बर, 2013 को प्रकाशित शीर्षक ''अबतक 1840 को डेंगू का डंक'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना शहर में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, परन्तु पटना नगर निगम द्वारा अभीतक कहीं भी मच्छर मारने हेतु फौगिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

*365. श्री वैद्यनाथ सहनी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड मोरवा के ग्राम पंचायत हरपुर भिन्डी, गुनाई बसही, मौड़ा खुर्द, बैना चकसिकन्दर, माड़ीपुर बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायत है एवं बाढ़ के दिनों में शुद्ध पेयजल अनुपलब्ध रहता है, यदि हाँ, तो उक्त स्थानों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

प्लांट पूरा कराना

*366. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण के पीपराखेम पैक्स में वर्ष 2008-09 में स्वीकृत मिनी राईस मिल-सह-गैसीफायर प्लांट को पूर्ण कराने हेतु विभाग द्वारा समय पर कारगर कदम नहीं उठाने के कारण आजतक अधूरा पड़ा है, यदि हां, तो सरकार कबतक इसे पूरा कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में पीपराखेम पैक्स, प्रखंड-कल्याणपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण में रु० 24 लाख की कुल लागत पर चावल मिल-सह-गैसीफायर की स्वीकृति दी गयी थी तथा नियमानुसार योजना लागत का 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध भी करा दिया गया था। शेष राशि की व्यवस्था पीपराखेम पैक्स को स्वयं अपने संसाधन से उपलब्ध कराना था। इसके विरुद्ध उनके द्वारा रु० 2.40 लाख का जमीन क्रय किया गया है और रु० 9.60 लाख का ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, मोतिहारी से मई, 2013 में प्राप्त किया गया।

वर्तमान में छत स्तर तक गोदाम का पैक्स का दीवार निर्मित है। उस पर एसवेस्टस नहीं डाला गया है। प्लास्टर का कार्य जारी है। जेनेरेटर का क्रय किया जा चुका है। गैसीफायर प्लांट स्थापित है राईस मिल संयंत्र के लिए अग्रिम का भुगतान

किया जा चुका है। अतः कार्य प्रगति पर है और विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई की गई है।

वाटर सप्लाई कराना

*367. श्री सतीश चन्द्र दुबे—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज नगर परिषद् में नगर परिषद् मुख्यालय में जमीन उपलब्ध होने के बावजूद आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी शुद्ध पेयजल हेतु पानी टंकी का निर्माण एवं आपूर्ति की व्यवस्था अभीतक नहीं हो सकी है ?

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त नगर परिषद् में वाटर सप्लाई कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कृषि महाविद्यालय खोलना

*368. श्री कृष्णनन्दन यादव—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मगध प्रमंडल में एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं है, यदि हां, तो इस हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। प्रशासनिक प्रमण्डल के आधार पर कृषि शिक्षा एवं शोध संस्थान की स्थापना की तुलना में कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर संस्थानों की स्थापना का वैज्ञानिक आधार है। कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार को तीन भागों में बाँटा गया है। मगध प्रमण्डल, पटना प्रमण्डल, भागलपुर प्रमण्डल एवं मुंगेर प्रमण्डल कृषि जलवायु क्षेत्र-3 के अधीन आता है। इस क्षेत्र में पहले से सबौर में एक कृषि महाविद्यालय, पटना में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय तथा एक डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापित थे। वर्ष 2006 के बाद इस क्षेत्र में एक नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सबौर में की गई है। इसी क्षेत्र में नालंदा में एक नये उद्यान महाविद्यालय तथा डुमराँव में एक नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। मगध प्रमण्डल सहित किसी अन्य प्रमण्डल में नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

राशि का वितरण

*369. श्री छोटेलाल राय—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत जिला में बगीचा बचाओ अभियान के तहद प्रखण्ड दरियापुर एवं परसा में जिला उद्यान पदाधिकारी, छपरा के

नाम वर्ष 2012-13 में किसानों के बीच अनुदान राशि वितरण के लिए दी गई थी, परन्तु उक्त राशि वितरित नहीं किया गया, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

सीमेंन उपलब्ध कराना

*370. श्री वीरेन्द्र सिंह—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के पशु चिकित्सालय में कृत्रिम गर्भाधान के लिए ''सीमेंन'' उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार सीमेंन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

पदस्थापन करना

*371. श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, खाद्य, उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखंड में विगत 2 वर्षों में विपणन पदाधिकारी (एम०ओ०) का पद रिक्त है, यदि हाँ, तो उक्त पदस्थापन हेतु सरकार की क्या योजना है ?

बैठक सुनिश्चित कराना

*372. श्री पवन कुमार जायसवाल—दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 फरवरी, 2013 को छपी खबर के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गरीबों को मिलने वाले राशन और किरासन के वितरण पर नजर रखने के लिए पंचायत स्तर पर 8442 निगरानी समितियां और अनुमंडल स्तर पर 101 अनुश्रवण समितियां बनाई गई है, परन्तु इन समितियों की नियमित बैठकें नहीं होती है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी बैठक की सूचना दिलवाने एवं नियमित बैठक सुनिश्चित कराने का विचार रखती है ?

पानी टंकी चालू कराना

*373. श्री (मो०) आफाक आलम—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखंड के पानी टंकी दो वर्ष से बनकर तैयार है, जिसे अभीतक चालू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

आनाज की आपूर्ति

* 374. श्री सदानन्द सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड में एस० एफ० सी० गोदाम है, परन्तु माह जुलाई, 2013 से जन–वितरण प्रणाली की अनाज की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोराडीह प्रखंड को वर्तमान समय में भागलपुर एफ० सी० आई० गोदाम से अनाज की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है जो समय पर अनाज की आपूर्ति नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

* 375. श्री आनन्दी प्रसाद यादव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के पलासी प्रखंड मुख्यालय में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु जलमीनार का निर्माण वर्ष 2009 में की गयी है, किन्तु अभीतक उक्त जलमीनार से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जलमीनार से कबतक लोगों को शुद्ध पेय जल मुहैया कराने का विचार रखती है ?

पैक्स सदस्य बनाना

* 376. श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक 1313, दिनांक 25 मार्च, 2013 द्वारा वर्ष 2013–14 को पैक्सों में सदस्यता वृद्धि अभियान वर्ष घोषित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभियान के दौरान प्रत्येक पैक्स में कम–से–कम एक हजार सदस्य बनाये जाने हैं, यदि हाँ, तो सारण जिला में इस योजना को शुरू नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

शिकायतों का निपटारा

* 377. श्री अनिल सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम में कुल 18 हजार शिकायती मामले निपटारा हेतु लम्बित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिकायत संख्या 73 बी० /12, दिनांक 26 सितम्बर, 2012 एवं पिछले एक वर्ष में लम्बित 2 हजार मामले में एक बार भी नगर आयुक्त द्वारा सुनवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिकायत संख्या 73 बी०/12, दिनांक 26 सितम्बर, 2012 के साथ–साथ अन्य शिकायतों का एक समय–सीमा के अंदर अविलम्ब निपटारे का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गेहूँ वितरण कराना

* 378. श्री जवाहर प्रसाद––क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम मुख्यालय के सासाराम नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत अप्रैल, 2013 से ए0 पी0 एल0 परिवारों को राशन नहीं मिल रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सासाराम नगर परिषद् क्षेत्र में कुल ए0 पी0 एल0 परिवारों की संख्या 16,196 है ;

(3) क्या यह बात सही है कि ए0 पी0 एल0 परिवार के लोग महंगे दर पर बाजार से गेहूँ खरीदने पर मजबूर हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ए0 पी0 एल0 परिवारों के सदस्यों को गेहूँ वितरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन की योजना

* 379. श्री रामदेव महतो––क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के मधुबनी अनुमंडल में डी0 सी0 एल0 आर0 का पद विगत 1 साल से रिक्त है, यदि हाँ, तो उक्त पदस्थापन हेतु सरकार की क्या योजना है ?

धान की अधिप्राप्ति

* 380. श्री राजेश्वर राज––क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट, विक्रमगंज एवं सझौली सहित अन्य प्रखंडों में मालगुजारी रसीद के अभाव में माह जून, 2012 से ही राजस्व वसूली ठप है, जिससे किसानों को धान अधिप्राप्ति में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मालगुजारी रसीद उपलब्ध कराते हुए राजस्व वसूली एवं धान अधिप्राप्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूर्ण कराना

* 381. श्री राजकुमार राय––क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर विधान–सभा के हसनपुर प्रखंड के ग्राम–बगराहा एवं दाथ में ग्रामीण जलापूर्ति योजनान्तर्गत मिनी जलमीनार निर्माण कार्य तीन वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया जो अभीतक पूर्ण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो कबतक सरकार उक्त कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

पेयजल पम्पों को अधिष्ठापित करना

* 382. श्री अजय प्रताप——क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि——

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में सोलर चालित 10, डीजल चालित 20 एवं ऊर्जा चालित 38 स्थानों पर पेयजल आपूर्ति हेतु पम्प अधिष्ठापित करने का प्रावधान किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा इस संदर्भ में मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पत्र के माध्यम से दिसम्बर, 2012 में शिकायत करने के बावजूद भी अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सोलर चालित, डीजल चालित एवं ऊर्जा चालित पेयजल पम्पों को अधिष्ठापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन पर कब्जा दिलाना

* 383. श्री विनय बिहारी——क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि——

(1) क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत सन् 1995 से 2013 तक भूमिहिनों के बीच जिला प्रशासन ने 35 हजार परिवारों के बीच वासगीत का पर्चा वितरित किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन द्वारा वितरित वासगीत के पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया है, जिसके कारण पिड़ित परिवार सडकों के किनारे गुजर बसर कर रहे हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विस्थापितों के मिले वासगीत के पर्चे वाली जमीन पर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

* 384. श्री सबा जफर——क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि——

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के अमौर प्रखण्ड में प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का पदस्थापन छः माह से नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कृषि पदाधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण प्रखण्ड कृषि कार्य बाधित है ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का पदस्थापन कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

* 385. श्री आनन्दी प्रसाद यादव——क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि——

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत भरगामा अंचल में चरैया राजस्व हाट का भू–भाग आवासीय निर्माण से बुरी तरह अतिक्रमित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007–08 में तत्कालीन अंचलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने हेतु सरकारी स्तर से मापी भी कराया था और बडे पैमाने पर हाट का भू–भाग अतिक्रमित पाया था, किन्तु अतिक्रमण से हाट को मुक्त नहीं कराया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त हाट को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*386. श्री श्याम बिहारी राम --क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखण्ड के गोला रोड के वार्ड नं० 21 में झखरी महादेव मंदिर के पीछे डाक्टर चौबे से दक्षिण की ओर जानेवाली सड़क विरेन्द्र राय के मकान से नागेश्वर सिंह के मकान तक जिसमें सैकड़ों मकान अवस्थित हैं, परन्तु अभीतक न सड़क का सोलिंग की गयी है और न जल निकासी की व्यवस्था है जिससे आमजनों को काफी असुविधा होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि मुहल्लावासियों द्वारा क्रमशः श्री जमादार राय, श्री राम इकबाल सिंह, किशोरी साव, श्री हीरालाल राम एवं श्री अशोक राम सहित 25 व्यक्तियों द्वारा जिलाधिकारी, पटना एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर को विगत तीन वर्षों से अनेकों आवेदन दिया गया, परन्तु अबतक इसपर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खण्ड (1) में वर्णित सड़क का पक्कीकरण एवं जल निकासी हेतु सरकार कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतन एवं पेंशन का भुगतान

*387. श्री रत्नेश सदा-- क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सचिव, सहकारिता विभाग के पत्रांक 1941, दिनांक 8 सितम्बर, 1977 एवं ज्ञापांक 2000, दिनांक 22 सितम्बर, 1977 द्वारा विशेष नियोजन योजनान्तर्गत पैक्स प्रबंधकों की नियुक्ति जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा-सुपौल सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मधेपुरा के दिनांक 4 जून, 2003 से परिसमापन के कारण कोसी प्रमण्डल, सहरसा के 245 पैक्स प्रबंधकों का वेतन भुगतान कई वर्षों से लम्बित है;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग के पत्रांक 2041 सं० को०, दिनांक 14 नवम्बर, 2011 के आलोक में भुगतान संबंधी प्रतिवेदन समर्पित होने के बावजूद भी आजतक भुगतान नहीं हो रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रभावित कर्मियों को बकाया वेतन एवं पेंशन आदि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवंटित कर भुगतान करना

*388. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सितम्बर, 2013 में जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा डीजल अनुदान की शेष राशि वितरण हेतु 36 लाख रुपये की माँग सरकार से की गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिले के अन्य प्रखण्डों की तरह सन्हौला प्रखण्ड में भी किसानों के डीजल अनुदान की राशि बाकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र डीजल अनुदान के बकाये राशि के भुगतान हेतु राशि आवंटित कर भुगतान करने का विचार रखती है, तो कबतक ?

क्रय केन्द्र नहीं खोलने का औचित्य

''ख''*389. श्री संजय सिंह ''टाइगर'' --स्थानीय हिन्दी दैनिक में दिनांक 23 नवम्बर, 2013 को प्रकाशित शीर्षक ''किसान पूछ रहे, कब होगी धान की खरीदारी'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के किसानों का धान खेत से खलिहान में आ गया है, लेकिन बिहार के किसी जिले में अभीतक धान क्रय केन्द्र नहीं खोले गये हैं, जबकि सरकार के घोषणा के अनुसार दिनांक 15 नवम्बर, 2013 से क्रय केन्द्र प्रारम्भ करना था, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

नोट--''ख''--सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 5021, दिनांक 4 दिसम्बर, 2013 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में स्थानान्तरित ।

संवेदक पर कार्रवाई

*390. श्री अवधेश कुमार राय--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में जल प्रदूषण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु उच्च मानक चापाकल गाड़ने का प्रावधान किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में पूरे राज्य में 15,000 हजार में से बेगूसराय जिला 1,060 (एक हजार साठ) चापाकल गाड़ने हेतु मेमरान फोल्टर कम्पनी के साथ राज्य सरकार के साथ अनुबंध किया गया था;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय तक पूरे राज्य में 1,000 हजार तथा बेगूसराय जिला में 100 चापाकल भी नहीं गाड़ा गया है और संवेदक के द्वारा पूरे प्राक्कलन का 75 प्रतिशत राशि का निकासी कर लिया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिशीघ्र चापाकल गड़वाने के साथ ही उक्त संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यों को पूरा करना

*391. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला में आई०सी०डी०पी० योजनान्तर्गत पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण, राईस मिल्स, मिनी राईस मिल्स, एग्रो क्लीनिक, बैंकिंग हेतु काउंटर, गैसी फायर, मार्जिन मनी, जीर्ण-शीर्ण गोदामों की मरम्मती, बकरी पालन आदि के लिये राशि देने का सरकारी प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रावधान को सरकारी अधिकारियों द्वारा मात्र गोदामों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा अन्य ऊपर वर्णित कार्यों को छोड़ दिया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

व्यय की जाँच

*392. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्डान्तर्गत अथमलगोला के श्री मनोज कुमार यादव के सूचना के अधिकार अन्तर्गत माँगे गये उत्तर में कार्यपालक दंडाधिकारी, नगर पंचायत, मनिहारी ने अपने पत्रांक 258, दिनांक 4 अक्तूबर, 2013 द्वारा जनवरी, 2013 से जुलाई, 2013 तक कुल 1,27,60,805 रु० के व्यय की बात बतायी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त व्यय की जाँच कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*393. श्री (डा०) अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 8 अक्तूबर, 2013 के अंक में छपी खबर "1.37 करोड़ गरीबों को दुर्गा पूजा में राशन नहीं" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, नवादा, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया जिलों में अगस्त, 2013 का पूरा राशन नहीं बँटा तथा सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मधेपुरा, किशनगंज, मुंगेर, जमुई आदि 17 जिलों को सितम्बर, 2013 का पूरा अनाज नहीं मिला जिसके कारण 1.37 करोड़ गरीबों को राशन उपलब्ध नहीं हो सका;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 1.37 करोड़ गरीबों को राशन नहीं देने के लिये दोषियों पर कार्रवाई करते हुये बकाये अनाज को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कार्य शुरू कराना

*394. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना के कंकड़बाग टेम्पू स्टैंड से योगीपुर सम्प हाउस तक सड़क के दोनों किनारे 80 कियोस्क बनाने हेतु 30 लाख रुपये की स्वीकृति मई, 2008 में दिये जाने के बावजूद इसका निर्माण कार्य अबतक शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इन कियोस्क का निर्माण कार्य कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 (ई०) ।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

वि०स०मु० (एल०ए०)-111-450